

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी

नोटासीन अधिकारी—

अमानुल्लाह खान,
आर.ए.एस.

मिसल संख्या

तारीख दायरा

तारीख फैसला

165 / प्रा0पत्र / 17

13.04.2017

11.10.2021

सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

—प्रार्थी

बनाम

भंवरलाल आ0 हरजी जाति बैरवा निवासी अबड़ हाल निवासी वृद्धाश्रम के पास नैनवा रोड़ बून्दी जिला बून्दी।

—अप्रार्थी

उपरिस्थित—

प्रार्थी की ओर से—पेरोकार सरकार

अप्रार्थी की ओर से—श्री कुलदीप सिंह गौड़ एड0

निर्णय

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार हिण्डोली द्वारा अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम, 1970 इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अप्रार्थी भंवरलाल आ0 हरजी जाति बैरवा निवासी अबड़ तहसील हिण्डोली को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 129 रकबा 12.05 बीघा वाके ग्राम अबड़ आवंटन आदेश दिनांक 20.05.1981 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

बहस उभयपक्ष समाप्त की गई।

राजकीय अभिभाषक बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी गोपाल को विवादित कृषि भूमि खसरा संख्या 129 रकबा 12.05 बीघा वाके ग्राम अबड़ का आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक 20.05.1981 को किया गया था। आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जाकाशत नहीं रहा है। आवंटित भूमि पर देवी-देवताओं की छतरियां, श्मशान एवं ग्राम खेजड़ा से अबड़ आने-जाने का रास्ता बना हुआ है और वर्तमान में भूमि सार्वजनिक उपयोग में आ रही है। शेष भूमि पर अन्य व्यक्ति काबिजकाशत है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं कर आवंटन नियम 14(3) उल्लंघन किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आवंटन आदेश दिनांक 20.05.1981 को खारिज किया जावे।

वकील अप्रार्थी ने दोराने बहस तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थी भंवरलाल को आवंटन की पात्रता रखने से आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाकर भूमि का आवंटन किया गया है। आवंटन पूर्ण कोरम में किया गया है। अप्रार्थी आवंटनशुद्धा भूमि खसरा संख्या 129 रकबा 12.05 बीघा पर आवंटन से लेकर आज तक काबिज होकर काशत करता चला आ रहा है। तहसीलदार द्वारा आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही लगभग 36 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है जो अवधि बाधित है तथा चलने योग्य नहीं है। आवंटी वर्तमान में गैर-खातेदार कृषक है जिसे आज तक खातेदारी अधिकार नहीं दिये

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

नियमों में 10 वर्ष पश्चात खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने के निर्देश हैं।
संशोधित नियमों के अनुसार 3 वर्ष में खातेदारी अधिकार देने की अवधारणा की
है। अतः तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त कर आवंटन आदेश
दिनांक 20.05.1981 यथावत रखा जावे। वकील अप्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में
आरआरटी 2016(2) पेज 756 एच.सी., आरआरटी 2011(1) पेज 353 एच.सी., आरआरटी
2016(2) पेज 769 एच.सी., आरआरटी 2017(2) पेज 972, आरआरटी 2018(1) पेज 1007
की नजीरें प्रस्तुत की।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया।
हम प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना न्यायोचित समझते हैं। हस्तगत प्रकरण
में यह तथ्य प्रकट हैं कि अप्रार्थी भंवरलाल को आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक
20.05.1981 को आवंटन किया गया है। प्रार्थी द्वारा यह तथ्य व्यक्त किये गये हैं कि
अप्रार्थी का उक्त भूमि पर कब्जाकाशत नहीं रहा है। इस संबंध में पत्रावली में उपलब्ध
खसरा गिरदावरी संवत् 2071 का अवलोकन किया गया जिसमें खरीफ में तिल, ज्वार, रबी
में गेहूं की फसल अंकित हैं, उक्त भूमि का कुल रकबा 12 बीघा 5 बीस्वा हैं जिसमें से
खरीफ में 8 बीघा भूमि पर फसल की गई है और रबी में 5 बीघा भूमि पर फसल की गई
है शेष रकबा पड़त रहा है। इसके अलावा अन्य संवतों की खसरा गिरदावरी प्रार्थी अथवा
अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि आवंटित रकबे पर
कौनसे संवत में कौनसी फसल की गई है या भूमि पड़त रही है। पत्रावली में उपलब्ध
पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 03.05.2016 से यह जाहिर आया कि
आवंटित कृषि भूमि पर अलौटी भंवरलाल बैरवा का कब्जाकाशत नहीं है। उक्त भूमि
सार्वजनिक रूप से श्मशान, रास्ता व देवी-देवताओं के स्थान के रूप में उपयोग में ली जा
रही है तथा शेष काबिज काशत भूमि पर गोपालसिंह के कब्जे काशत में चली आ रही है।
उक्त तथ्यों से यह प्रमाणित है कि अप्रार्थी का उक्त भूमि पर आवंटन के समय से कब्जा
काशत नहीं रहा है न ही आवंटी द्वारा आवंटन नियमों में निहित शर्तों की पालना की गई
है। आवंटित भूमि सार्वजनिक उपयोग में ली जा रही है। आवंटी का आवंटित भूमि पर
कब्जा काशत नहीं होने एवं मौके पर रास्ता, श्मशान, देवी-देवताओं के स्थान बने होने से
उसे खातेदारी अधिकार भी प्रदत्त नहीं किये गये हैं। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक
दृष्टांत इस प्रकरण में चस्पा नहीं होते हैं।

अतएव: परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक
20.05.1981 निरस्त किया जाता है। पत्रावली फ़ैसलें में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल
दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय प्रति के भिजवाये जावे।

आदेश आज दिनांक 11.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त कलक्टर,
बूंदी (सू. 10)
बूंदी